(ख) यदि हां, तो इस निगम को क्रमशः वर्ष 1989-90, 1990-91, और 1991-92 की प्रथम छमाही के दौरान कुल कितना घाटा हुआ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस निगम द्वारा चलायी जा रही लगभग 4,000 बसों के लिए इसमें लगभग 4,3000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(घ) अक्टूबर, 1991 के दौरान इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या थी, और प्रशासनिक खर्चों को कम से कम करने और इसकी कार्यकुशलता में सुधार करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (सितम्बर, 91 तक) के दौरान हुआ कुल घाटा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	(लाख रु.)
1989-90	11984.56
1990-91 (अनन्तिम)	19748.35
अप्रैल से सितम्बर, 1991 (अनन्तिम)	10915.32

(ग) और (घ) 31-10-91 की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों की कुल संख्या 41,161 थी। प्रशासनिक खर्चों को न्यूनतम स्तर पर लाने के विचार से दिल्ली परिवहन निगम ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित पिछली बकाया रिक्तियों को भरने और मृतक कर्मचारियों के निकट संबंधियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्त करने के सिवाय और सभी भर्तियां बंद करने का निर्णय किया है।

सरकार, दिल्ली परिवहन निगम की उत्पादकता को बढ़ाने और प्रचालन की लागत कम करने, अधिक-उपाय लागू करने तथा अधिक राजस्व अर्जित करने और कार्यचालन घाटों को कम करने की दृष्टि से चोरी को रोकने के लिए इसके कार्य निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखे हुए हैं। दिल्ली परिवहन निगम अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए रूटों का भी युक्तिसंगत बना रहा है।

Pendng projects of Rajasthan

325. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) what is the number of projects/schemes pertaining to Rajasthan which are pending clearance with his Ministry at present and the progress made so far in each case; and

(b) what is the time that is likely to be taken by the Central Government in each case for approval and what are the reasons for delay if the case is pending for more than six months?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) and (b) References about various road and bridge schemes from Rajasthan pending with the Government are mentioned below alongwith their position:

(i) 4 schemes for conversion of State Roads into National Highways and 13 schemes to be taken up under the Economic and Inter-State Importance Programme. These proposals can be considered only after the finalisation of the 8th Plan.

(ii) 33 schemes proposed to be financed against the augmented Central Road Fund. These would be processed after actual augmentation of the Central Road Fund, which has not yet taken place.

(iii) 11 estimates for works on National Highways. Four estimates have been taken up for sanction, four are under examination, one sanction is under issue and for two estimates clarifications are awaited from the State.

Restructuring of Coal India Limited

326. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government have decided to restruct the Coal India Limited in order to beef up the functioning thereof;

(b) if so, what are the details thereof and also the reasons therefor;

(c) what was its production cost averaged per tonne of coal as against the realisation charges per tonne during the year 1989-90 and 1990-91;

(d) who fixes the coal price indicating the recommendations made in this regard by the Bureau of Industrial Costs and Prices; and

(e) whether it is a fact that Coal India Limited had lost hundreds of crores in gradation of coal whereby higher grade coal was passed out as inferior grade to collect money from beneficiary parties if so, what action has so far been taken by Government in this regard and if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI S. B. NYAMAGOUDA): (a) and (b) No such decision has been taken so far.

(d) Government fixes the price of coal on the recommendations of the Bureau of Industrial Costs and Prices.

(c) and (e) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत

327. डा० अब्दार अहमद : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत शोचनीय है ;

(ख) क्या सरकार ने कभी कोटा और झालावाड़ को जोड़ने वाले और इसके पश्चात् मध्य प्रदेश को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत की कभी समीक्षा की है ;

(ग) क्या राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने के लिए पाली के निकट चम्बल नदी पर एक पुल निर्माण किया जा रहा है और यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर दिया जाएगा ;

(घ) इसके पूरा होने का निर्धारित समय क्या था और विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इसके निर्माण में घटिया किस्म की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है; यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई जाएगी ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों को सामान्यतः यातायात योग्य स्थिति में रखा जा रहा है। कमियों वाले खंडों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के भीतर आवधिक नवीकरणों, सुदृढ़ीकरण आदि द्वारा क्रमिक सुधार किया जा रहा है ।

(ख) जी, हां । इस राष्ट्रीय राजमार्ग की दशा में समग्र प्राथमिकताओं और निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए सुधार किया जा रहा है । इस समय कुल 26.10 करोड़ रुपए के 38 कार्य चल रहे हैं । इसके अलावा, वार्षिक योजना 1991-92 में संस्वीकृति के लिए और कार्यों को शामिल किया गया है ।